भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5122

दिनांक 24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात में वृद्धि

5122. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है;
(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कब से दर्ज की जा रही है; और
(ग) सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ख) भारत का व्यापारिक कार्य-निष्पादन सुदृढ़ और स्थिर बना हुआ है, जिसके तहत वर्तमान वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26, अप्रैल-जनवरी) और दीर्घकालीन अवधि (वित्त वर्ष 2021-25) दोनों में निर्यात में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। वैश्विक अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और अस्थिर वस्तु कीमतों के बावजूद, भारत का निर्यात व्यापक रूप से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल-जनवरी के दौरान, पण्यवस्तु और सेवाओं का कुल निर्यात 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 5.26% की वृद्धि दर्शाते हुए वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जनवरी) के 679.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 714.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वर्ष 2021-22 से 2024-25 की अवधि में, निर्यात में 6.9% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य में वर्ष 2020-21 के 497.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 828.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक तीव्र वृद्धि हुई। यह निरंतर विस्तार भारत की विविध और सुदृढ़ निर्यात वृद्धि को बनाए रखने की क्षमता को रेखांकित करता है, जिससे चुनौतीपूर्ण बाहरी परिस्थितियों में भी देश वैश्विक व्यापार में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित होता है।

(ग) सरकार निर्यात को बढ़ावा देने और देश की वैश्विक उपस्थिति को विस्तारित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसमें पारंपरिक शक्तियों को उभरते प्रौद्योगिकी-आधारित क्षेत्रों के साथ जोड़ा जा रहा है। इस महत्वाकांक्षा का मूल उद्देश्य एक ऐसा सहायक इको-सिस्टम तैयार करना है जहां निर्यातक, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आत्मविश्वास से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस प्रयास को एक गतिशील नीतिगत फ्रेमवर्क, मजबूत वित्तीय प्रोत्साहन, बढ़ती डिजिटल अवसंरचना, बेहतर व्यापार सुविधा और अगली पीढ़ी के व्यापार समझौतों के माध्यम से बाजार तक गहरी पहुंच सुनिश्चित करने के दृढ़ प्रयास से बल मिल रहा है।

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 जिसे वैश्विक परिवर्तनों के अनुरूप एक लचीले और विकसित होते फ्रेमवर्क के रूप में डिजाईन किया गया है,, भारत की निर्यात गति को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। व्यापार सुगमता, निर्यात संवर्धन, राज्य स्तरीय साझेदारी और डिजिटल एकीकरण - इन चार मुख्य स्तंभों पर आधारित एफटीपी को लक्षित निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं द्वारा और भी मजबूत बनाया गया है, जो सामूहिक रूप से वैश्विक बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती हैं।

आरओडीटीईपी योजना निर्यात पर लगे करों को समाप्त करके और भारतीय वस्तुओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल ही में शुरू किया गया निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) दो लक्षित स्तंभों: किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच का विस्तार करना और निर्यात मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता, संभार तंत्र, ब्रांडिंग और बाजार-तत्परता को उन्नत करना, के माध्यम से इस प्रयास को और मजबूत करता है। सरकार ने 25,060 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक) के साथ ईपीएम को मंजूरी प्रदान की है। यह निर्यात प्रोत्साहन (व्यापार वित्त और ऋण संवर्धन पर केंद्रित) और निर्यात दिशा (निर्यात संभार तंत्र, भंडारण और बाजार पहुंच पर केंद्रित) के माध्यम से परिचालित होता है, जिसका विशेष लक्ष्य एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

सरकार ने हाल ही में एक समयबद्ध "आरईएलआईईएफ" योजना अधिसूचित की है, जो निर्यात संवर्धन मिशन के तहत एक क्रियाकलाप है। इसे भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, और इसे खाड़ी एवं पश्चिम एशिया समुद्री गलियारे में भू-राजनीतिक व्यवधानों से उत्पन्न बढ़ते निर्यात जोखिमों से निपटने के लिए संचालित किया गया है।

निर्यात के लिए महत्वपूर्ण जोखिम-निवारण सहायता प्रदान करने वाले निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) और व्यापार अवसंरचना निर्यात योजना (टीआईईएस) जैसी योजनाओं के साथ मिलकर काम करना जो देश भर में निर्यात से जुड़ी अवसंरचना का निर्माण करती है।

इन वित्तीय और नीतिगत साधनों के समानांतर, भारत प्रौद्योगिकी-आधारित व्यापार गवर्नेंस की ओर तेजी से अग्रसर है। 24×7 ईआईसी इंटरफेस, ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, उत्पत्ति प्रमाण पत्रों हेतु कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म और ट्रेड ई-कनेक्ट पोर्टल जैसे प्लेटफार्मों द्वारा संचालित एक मजबूत डिजिटल आधार ने निर्यातकों के सूचना, अनुमोदन और वैश्विक बाजारों तक पहुंच के तरीके को बदल दिया है। ये प्रणालियां पूरी तरह से ऑनलाइन प्रसंस्करण, रियल टाईम अनुपालन संबंधी अपडेट, डिजिटल प्रमाणीकरण, त्वरित प्रक्रिया और वैश्विक बाजार की जानकारी तक आसान पहुंच को सक्षम बनाती हैं। इसका परिणाम एक ऐसा व्यापार इको सिस्टम है जो अधिक पारदर्शी, डेटा-आधारित, कुशल और न्यायसंगत है।

अग्रसक्रिय व्यापार कूटनीति नीतिगत उपायों और विस्तारित डिजिटल अवसंरचना का पूरक है, जो वैश्विक बाजार तक पहुंच को मजबूत करने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के देश के प्रयासों को बल देती है। 19 मुक्त व्यापार समझौतों और वर्ष 2021 से नए सिरे से किए गए प्रयासों के साथ, भारत ने प्रमुख साझेदारों के साथ आठ बड़े समझौतों को अंतिम रूप दिया है या उन्हें आगे बढ़ाया है। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, जो लगभग पूरे यूरोपीय संघ के टैरिफ क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ऐतिहासिक समझौता है, भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में और अधिक गहराई से एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें निवेशकों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ाने के उद्देश्य से एक समर्पित प्रतिबद्धता शामिल है। न्यूजीलैंड, ओमान और ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते बाजार पहुंच को व्यापक बनाएंगे, सेवाओं की मोबिलिटी को बढ़ाएंगे, दीर्घकालिक निवेश सुरक्षित करेंगे और व्यवसायों के लिए पूर्वानुमानित नियामक वातावरण का निर्माण करेंगे। इस बीच, इज़राइल, कनाडा, जीसीसी देशों, चिली और पेरू के साथ चल रही वार्ताएं विभिन्न क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाले व्यापार गलियारों का विस्तार करने के भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं।

भारत की निर्यात कार्यनीति एक निर्णायक समग्र सरकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो व्यापारिक सहयोग से आगे बढ़कर एक लचीला, प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार इको-सिस्टम तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है। लक्षित वित्तीय प्रोत्साहनों, प्रौद्योगिकी-सक्षम व्यापार सुगमता, संस्थागत सुधारों और अग्रसक्रिय बाजार पहुंच पहलों के संयोजन से, डिजिटल गवर्नेंस को सुदृढ़ करने, वैश्विक पहुंच का विस्तार करने और विभिन्न क्षेत्रों में निर्यातकों की क्षमताओं को मजबूत करने पर फोकस किया

गया है। यह एकीकृत दृष्टिकोण भारत को न केवल एक भागीदार के रूप में, बल्कि वैश्विक व्यापार में एक विश्वसनीय, प्रौद्योगिकी-संचालित साझेदार के रूप में स्थापित करता है।

*****